भारत सरकार
शिक्षा मंत्रालय
स्कूल शिक्षा और साक्षारता विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या- 2432
उत्तर देने की तारीख 04/08/2025

एनईपी 2020 की सिफारिशें

†2432. **श्री राजेशभाई नारणभाई चुडासमा:**

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:
(क) क्या सरकार की वर्ष 2030 तक माध्यमिक स्तर पर शत-प्रतिशत सकल नामांकन अनुपात (जीईआर) प्राप्त करने के लिए एनईपी, 2020 की सिफारिशों को कार्यान्वित करने की कोई योजना है;
(ख) यदि हां, तो इन सिफारिशों के अंतर्गत उठाए गए कदमों और उनकी प्रगति का ब्यौरा क्या है; और
(ग) इन लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु योजनाओं का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री जयन्त चौधरी)

(क) से (ग): राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी), 2020 के पैरा 3.1 में कहा गया है कि "*...इन बच्चों को यथासंभव शिक्षा प्रणाली में पुन: शीघ्र वापस लाना सर्वोच्च प्राथमिकता होगी। इसके साथ ही* 2030 *तक प्री-स्कूल से माध्यमिक स्तर में* 100% *सकल नामांकन अनुपात प्राप्त करने के लक्ष्य के साथ भविष्य में छात्रों की ड्रॉपआउट दर को कम करना होगा। प्री-स्कूल से कक्षा* 12 *तक व्यावसायिक शिक्षा सहित गुणवत्तापूर्ण समग्र शिक्षा प्राप्त करने हेतु देश के सभी बच्चों की सार्वभौमिक पहुँच सुनिश्चित करने और अवसर प्रदान करने के लिए एक ठोस राष्ट्रीय प्रयास किया जाएगा।*"

एनईपी 2020 में सभी बच्चों के लिए शिक्षा तक पहुँच सुनिश्चित करने के महत्व का उल्लेख किया गया है और शिक्षा के विभिन्न स्तरों पर सकल नामांकन अनुपात (जीईआर) में सुधार के लिए एक महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इस नीति के उद्देश्य की प्राप्ति के लिए, स्कूल शिक्षा के विभिन्न क्षेत्रों यथा बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान, स्कूल परिसरों/क्लस्टरों के माध्यम से कुशल संसाधन और प्रभावी अभिशासन, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा: बुनियादी चरण, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा-स्कूल शिक्षा, कौशल विकास, राष्ट्रीय क्रेडिट

रूपरेखा (एनसीआरएफ), डिजिटल प्रौद्योगिकी, अपार आईडी, समग्र शिक्षा, अवसरंचनात्मक विकास के लिए अन्य मंत्रालयों के साथ अभिसरण, पीएम श्री, पीएम ई-विद्या चैनलों और दीक्षा के माध्यम से पहुंच में सुधार, शिक्षक प्रशिक्षण, सार्वजनिक निजी भागीदारी, समता और समावेशन-कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय (केजीबीवी); पीएम जनमन और डीएजेगुआ, मूल्यांकन और पीएम पोषण आदि जैसे महत्वपूर्ण प्रयास किए जा रहे हैं। इन क्षेत्रों में किए गए संचयी प्रयासों ने 100% जीईआर के लक्ष्य प्राप्ति में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।

प्रारंभिक शिक्षा तक लगभग सार्वभौमिक पहुँच प्राप्त करने में उल्लेखनीय प्रगति हुई है और एनईपी 2020 के उद्देश्य के अनुसरण में प्री-स्कूल से माध्यमिक स्तर तक 100% जीईआर लक्ष्य प्राप्ति हेतु विभिन्न लक्षित पहलें की जा रही हैं। इसके अतिरिक्त, पिछले एक दशक में, समग्र शिक्षा जैसी केंद्र प्रायोजित योजनाओं और राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र स्तर पर विभिन्न पहलों के माध्यम से स्कूल शिक्षा सुविधाओं को परिपूर्ण करने में व्यापक प्रगति हुई है। इन पहलों का प्रभाव बढ़ती नामांकन दरों, स्कूल छोड़ने वालों की संख्या में कमी, बेहतर अवसरंचना और बेहतर शैक्षणिक प्रदर्शन के रूप में स्पष्ट है। प्राथमिक स्तर पर सकल नामांकन अनुपात (जीईआर) 93%, उच्च प्राथमिक स्तर पर 89.7% और माध्यमिक स्तर पर 77.4% तक पहुँच गया है।

सरकार और राज्य की पहलें सामाजिक-आर्थिक रूप से वंचित समूहों के लिए शैक्षिक पहुंच का भी उल्लेखनीय विस्तार करती हैं। समग्र शिक्षा योजना महत्वपूर्ण आवासीय सुविधाएं प्रदान करके पारंपरिक स्कूल शिक्षा से परे शैक्षिक पहुंच का विस्तार करती है। इसमें सामाजिक-आर्थिक रूप से वंचित समूहों के बच्चों के लिए महत्वपूर्ण कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय (केजीबीवी), नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवासीय विद्यालय (एनएससीबीएवी), प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान (पीएम जनमन) और धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान (डीएजेगुआ) शामिल हैं।

******